

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर०एम०न०-26/2011-12

मु० मुर्शीद वगैरह

वनाम

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

आदेश

दिनांक 8/2/2012

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखित कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्ता मु० मुर्शीद पे० शेख असगर व० मु० सज्जाद, पे० शेख असगर व० मु० असगर, पे० शेख जुम्मान मंडल, सा०-जगतपुर, अदल-बसंतगढ़, जिला-गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर०ई०आर० केश नं०-74/2009-10(संजली दुहू वनाम शेख मुर्शीद वगैरह) आदेश दिनांक-23.07.2011 के विरुद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्तागण का कथन है कि वादगत जमीन मौजा-जगतपुर, जमाबंदी नं०-70 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में लखन दुहू व० टीका दुहू व० बरिया दुहू व० राम दुहू व० पैरु दुहू पेशवान डेनडा दुहू व० किशुन दुहू पे०-लखन दुहू के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रयत बरियान दुहू को तीन पुत्र क्रमशः जेटा दुहू, मंगल दुहू एवं लाल दुहू हुए। इनमें से लाल दुहू की मृत्यु नावलद हो गई है। उत्तरवादी संजली दुहू अपने को जेटा दुहू की पुत्री एवं गत जमाबंदी रयत बरियार दुहू की पोती बताते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पुरक) अधिनियम-1949 की धारा-20 एवं 40 के तहत वादगत जमीन से अपीलकर्ता को उच्छेद करने के लिए वाद दायर किया। निम्न न्यायालय के उच्छेदी वाद में अपीलकर्ता की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया कि उत्तरवादी द्वितीय पक्ष संजली दुहू अपने परिवार को छोड़कर रघु यादव से शादी कर ली है। आवेदिका उस जमाबंदी को वंशज नहीं रही क्योंकि उस जमाबंदी में पुरुष उत्तराधिकारी है एवं पुरुष उत्तराधिकारी के रहते महिला को अपने पिता की सन्यति कर कोई अधिकार नहीं बनता है। उनके द्वारा कारण-पृच्छा में यह भी उल्लेख किया गया कि वादगत जमीन पर अपीलकर्ता का पुराना आवासीय मकान है एवं उस पर उनका दखल 1949 के बारह वर्ष पूर्व से लगातार चला आ रहा है और

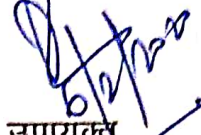
दखल के आधार पर अपीलकर्ता को उस जमीन पर अधिकार प्राप्त हो गया है इसलिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम-1949 की धारा-40 एवं 40 लागू नहीं होगा। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्ता के इन सारी तथ्यों पर विचार किये बिना ही अपीलकर्ता को वादगत जमीन से उच्छेद करने के लिए नियम के विपरीत आदेश पारित किया है। अपीलकर्ता ने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी राज्य की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है। उनका कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा मौजा-जगतपुर के जमाबंदी नं०-70 के दाग नं०-359 रकबा-00-02-05 धुर जमीन से अपीलकर्ता को उच्छेद किया गया है। क्योंकि उक्त जमीन गत सर्वे के अनुसार रैयती जमीन है और संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम-1949 की धारा-20 के प्रावधान के अनुसार रैयती जमीन का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता ने वादगत जमीन को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम -1949 की धारा-20 का उल्लंघन कर अवैध दंग से दखल कर लिया है। इस लिए निम्न न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। उन्होंने अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों, अंचल अधिकारी, बसंतराय से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा-जगतपुर जमाबंदी नं०-70 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में लखन दुडू वो टीका दुडू वो बरिआर दुडू वो राम दुडू वो पारु दुडू पेशरान डेमडा दुडू वो किशुन दुडू वल्द लखन दुडू के नाम से दर्ज है। अपीलकर्ता ने वादगत जमाबंदी नं०-70 के दाग नं०-359 रकबा-00-02-05 धुर जमीन प्राप्त करने का दावा किया है और उनका यह दावा है कि प्रतिकुल प्रभाव से उनका उस जमीन पर दखल होने के कारण उनका अधिकार कायम हो गया है। लेकिन उन्होंने सादा कुर्फा कागजात के अलावा प्रतिकुल प्रभाव से दखल होने का कोई भी साक्ष्य जनित कागजात दाखिल नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट है कि अपीलकर्ता का दखल अवैध है और यह संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम-1949 की धारा-20 के विपरीत है। इस आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय का आदेश का समर्थन करते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
गोडडा।


उपायुक्त,
गोडडा।

DV No. - 24

05/06/2020